बजट भाषण का प्रारूप–2017–18

माननीय अध्यक्ष जी,

1. मैं वर्ष 2017–18 के लिए बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लिए यह प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है कि मैं लगातार तीसरी बार इस सम्मानित सदन में बजट पेश कर रहा हूँ।

2. अध्यक्ष जी, अपने बजट वक्तव्य में, मैं दिल्ली की जनता की मेहनत की कमाई का सदुपयोग करने की दिशा में सरकार की योजनाओं पर बात रखूंगा। दिल्ली की जनता के पैसे का, जनता के लिए इस्तेमाल करते हुए आने वाले वर्ष में सरकार के विजन और प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करूंगा। साथ ही विगत दो वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सामाजिक सुरक्षा और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति का संक्षिप्त विवरण भी रखना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले आगामी वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किये जा रहे इस बजट की दो बेहद खास बातों का मैं उल्लेख करना चाहूंगा।

- पहली खास बात तो यह है कि इस बजट को हमने प्लान और नॉन– प्लान जैसे परंपरागत सांचों से निकालकर तैयार किया है। मैंने पिछली बार भी अपने बजट भाषण में इसका जिक्र किया था कि प्लान और नॉन–प्लान खर्च आम आदमी की समझ से परे की बातें हैं। उसके लिए तो सारा बजट ही सरकार का खर्च है। तो इस बार का बजट महज कैपिटल और रेवेन्यू दो हिस्सों में ही बंटा है। यानी, आम लोग अब आसानी से समझ सकेंगे कि जो योजनाएं और प्रोजेक्ट सरकार लोगों के लिए ला रही है, उनके शुरू होने पर कितना खर्च होगा और उन्हें आगे चलाने पर कितना खर्च होगा।

- दूसरी खास बात यह है कि इस वर्ष से हम 'आउटकम बजट' प्रस्तुत करेंगे। बजट एकाउंटिबिलिटी की बातें तो हम हमेशा से सुनते रहे हैं लेकिन आउटकम बजट उसके आगे की अवधारणा है जो देश में पहली बार किसी राज्य के बजट में अपनाई जा रही है। इसका विस्तृत विवरण मैं आगे रखूंगा लेकिन फिलहाल एक उदाहरण से इसे समझाना चाहूंगा – मान लीजिए मोहल्ला क्लीनिक बनाने में 20 लाख रुपये खर्च करके हम ये देखते हैं कि बिल्डिंग बनी या नहीं बनी। यह बजट एकांउटेबिलिटी है लेकिन बजट आउटकम में अब हम ये भी शामिल कर रहे हैं कि बिल्डिंग बनने के बाद इससे कितने लोगों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह उसका आउटकम होगा। इस आउटकम की मॉनिटरिंग हर एक तिमाही में की जाएगी।

3. अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में मुझे तीसरी बार दिल्ली सरकार का पूर्ण बजट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी सरकार का मूल कार्य है– लोगों को आसानी से जीने के लिए अवसर और वातावरण प्रदान करना। ऐसे अवसर और वातावरण बनाना ताकि लोग स्वस्थ रहते हुए बेहतरीन शिक्षा हासिल कर समाज में उत्पादन अथवा सेवा की अपनी भूमिका निभा सकें और अपने परिवार के लिए भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था गरिमापूर्ण तरीके से कर सकें। सरकार की सफलता का मतलब है लोग भयमुक्त हों और शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की असुरक्षा में न जियें। मुझे खुशी है कि पिछले दो बजट के दौरान हमने इस दिशा में जो विजन सदन के समक्ष रखा, उसके परिणाम महज दो वर्ष में ही सामने आने लगे हैं। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस सरकार के काम के प्रति लोगों की उत्सुकता बनी है।

4. ऐतिहासिक निर्णय करते हुए हमारी सरकार ने हाल ही में अकुशल, अर्ध–कुशल और कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में करीब 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अकुशल मजदूर को अब 9,724 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 13,350 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अर्धकुशल श्रमिकों को 10764 रूपये प्रतिमाह की जगह 14698 रूपये और कुशल कार्मिकों को 11830 की जगह 16182 रूपये प्रतिमाह मिलेंगे। यह देश में पहला अवसर है जब न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया है।

5. इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन में सहयोग के लिए कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में 1,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है। विकलांग जनों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि भी 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह की गई है।

6. एक नए और प्रायोगिक उपाय के रूप में हमारी सरकार ने बेघरों के लिए 10 रैन–बसेरों में कौशल विकास कोर्स शुरू किए हैं। इन कोर्सों में सिलाई, खाना पकाना, सौंदर्य प्रसाधन सेवाएँ और प्लम्बर के काम का प्रशिक्षण शामिल है। प्रत्येक रैन–बसेरे में 25 बेघरों के एक बैच को प्रशिक्षित किया जायेगा और 120 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करने पर प्रमाणपत्र दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के बाद इसका विस्तार अन्य रैन–बसेरों में किया जायेगा। समूचे शहर में करीब 266 रैन बसेरे हैं, जिनमें 21724 बेघरों के लिए ठहरने की व्यवस्था है। इस तरह गरीब और बेघर व्यक्ति गरिमापूर्वक अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकते हैं। सरकार ने रैन–बसेरों में मोहल्ला क्लिनिकों के जरिए चिकित्सा देखभाल सुविधा भी प्रदान की है।

7. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निर्धारित 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिला देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव उपाय किए हैं। इसके लिए दाखिला प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। हमने प्राइवेट स्कूलों के फीस के ढॉचे को रेगुलेट करने के लिए भी कड़े उपाय किए हैं। इन स्कूलों के खातों की लेखा–परीक्षा कराई गई और इसका ऐतिहासिक नतीजा यह हुआ कि कई स्कूलों ने बढ़ी हुई फीस वापस ले ली और वसूल की गई अधिक राशि अभिभावकों को रिफंड करना शुरू कर दिया।

8. इसी तरह हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले के तहत, सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे अतिथि शिक्षकों के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि की है। अभी तक अतिथि शिक्षकों को 700 से 900 रूपये प्रति कार्य दिवस की दर से 17 से 21 हजार रूपये के बीच प्रतिमाह मिलता था और इस माह से उन्हे 1000 से 1445 रूपये प्रति कार्य दिवस की दर से एक माह में 25 सामान्य कार्य दिवस के हिसाब से 25 से 36 हजार रूपये प्रतिमाह के बीच मिलेगा। इससे अध्यापक शिक्षण के प्रति संकल्पबद्ध और प्रेरित होंगे।

9. दिल्ली में हर अमीर और गरीब के लिए बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था करना, हर अमीर और गरीब के लिए बेहतरीन चिकित्सा की व्यवस्था करना, हमारी सरकार ने पिछले दो वर्षों में अपने प्रमुख लक्ष्यों में रखा था। सरकारी स्कूलों में नये कमरे बनवाना। हर स्कूल में पेयजल, साफ–सुथरे टॉयलेट की व्यवस्था करने के लक्ष्य में हम कामयाब हुए हैं। इतना ही नहीं, स्कूलों में पढ़ाई की क्वालिटी में सुधार लाते हुए हमने अपने प्रधानाचार्यों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग दिलाना शुरू कर दिया है। मेंटर टीचर्स को सिंगापुर भेजा जा रहा है। आईआईटी और आईआईएम जैसी देश की नामी संस्थाएं शिक्षा का स्तर सुधारने में हमारी मदद कर रही हैं। शिक्षा के लिए समर्पित प्रथम, साझा, क्रिएटनेट, जोड़ो ज्ञान जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर हमने बच्चों के अंदर रीडिंग एबिलिटी विकसित करने पर काम किया और 1 लाख से अधिक बच्चों के अंदर अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ने की योग्यता विकसित करने में सफलता हासिल की।

10. हमने स्नातक स्तर तक पढ़ाई के लिए 9 नये वोकेशनल कॉलेज शुरू किये जिससे हायर एजुकेशन में 2700 सीटें नई जुड़ीं। हमारा वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर 1000 बच्चों को देश में सबसे बेहतरीन स्किल ट्रेनिंग दे रहा है। कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे इसके लिए 10 लाख रुपये तक के लोन लेने की गारंटी सरकार ले रही है। इसी तरह, दिल्ली के हर नागरिक के मन में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भरोसा जगाने में 'मोहल्ला क्लीनिक' एक सफल प्रयोग रहा है, जहां महज 110 मोहल्ला क्लीनिक्स में 26 लाख लोगों ने फायदा उठाया है। अस्पतालों में 10,000 नये बेड्स का इंतजाम होने से लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति संतुष्टि स्तर बढ़ेगा। लेकिन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप के नये प्रयोग किये हैं जिसके तहत दिल्ली में पहले से मौजूद प्राइवेट क्लीनिक्स, टेस्ट सेंटर्स और हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को उपलब्ध कराने के लिए लिंक कर दिया गया है। इससे जिस टेस्ट या ऑपरेशन के लिए सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीज को कई–कई महीने और कई बार तो साल बाद की डेट मिलती थी, अब उन्हें कुछ दिनों में ही टेस्ट या ऑपरेशन की डेट मिल रही है।

11. शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था के प्रति भरोसा लोगों के अंदर असुरक्षा कम करता है और मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने पिछले दो वर्ष में लोगों के अंदर से इस असुरक्षा के भाव को काफी हद तक कम किया है। इसी तरह, बिजली के दामों में 50 परसेंट की कमी, 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी की सुविधा से लोगों को हर महीने आर्थिक लाभ पहुंचा है जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता सुधारने में हमें कामयाबी मिली है। साथ ही, लोगों में बिजली और पानी को सहेजकर रखने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। आज दिल्ली में बिजली की कोई कमी नहीं है। और पीने के पानी की स्वच्छता के स्तर को हम इस स्तर तक ले जा रहे हैं कि लोग खुद अपना नल खोलकर सीधे दिल्ली जल बोर्ड की स्पलाई का पानी पी सकें। इसकी ऐतिहासिक शुरूआत हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड के 11 जोन से की गई। इन 11 जोन्स में आने वाली कालोनियों के घरों में नल से सप्लाई होने वाले पानी की स्वच्छता की गारन्टी दिल्ली जल बोर्ड लेता है। धीरे धीरे यही गारन्टी पूरी दिल्ली की सभी कालोनियों में लाने पर कार्य चल रहा है।

12. शहर की गति बढ़ाने के लिए फ्लाईओवर्स के निर्माण का काम तेजी से पूरा किया है। इससे पश्चिमी दिल्ली से वजीराबाद तक पहुंचने में लगने वाला समय काफी कम हो गया है। बारापुला फेस–3 और मेट्रो फेस–3 का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। मेट्रो फेस–4, लोनी बॉर्डर से वजीराबाद तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। इन पर भी तेजी से काम शुरू हो जाएगा।

13. वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा अनेक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, जिनके पास लाभार्थियों का अलग–अलग डेटाबेस है। हमारी सरकार ने आधार, आयकर पैन, मतदाता फोटो पहचान पत्र आदि के मौजूदा डेटाबेस को एकीकृत कर एक कॉमन डेटाबेस बनाया जा रहा है। इस कॉमन डेटाबेस की सीडिंग जन सेवाओं के वितरण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे विभागीय डेटाबेस के साथ की जायेगी। इससे लाभार्थियों की सही पहचान की जा सकेगी और सेवाओं के वितरण में समय और लागत में कमी आयेगी। इस विशिष्ट डेटाबेस से सृजित आंकड़ो का इस्तेमाल नए कल्याण कार्यक्रमों की आयोजना के लिए किया जायेगा, जिससे कल्याण सेवाओं में दोहरेपन से बचा जा सकेगा।

14. इन सब बातों का उल्लेख इसलिए किया ताकि आगामी वित्त वर्ष के बजट को भी हम 'लोगों के आसानी से जीवन जीने में सहयोग' के रूप में समझ सकें।

आर्थिक परिदृश्य

15. अध्यक्ष जी, इस बार नोटबंदी के कारण राज्य के आर्थिक परिदृश्य में अंतिम 4 महीनों में काफी नकारात्मक रूझान देखने को मिल रहा है। मैंने कमोडिटी वाईज आंकड़े देखे हैं कि किस तरह अधिकतर बाजारों में नोटबंदी के कारण आर्थिक तंगहाली की स्थिति बनी है। मैं समझता हूं कि इसके दूरगामी असर अगले वित वर्ष में भी देखने को मिलेगें। लेकिन नोटबंदी के नकारात्मक प्रभाव के बावजूद, दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर 2016–17 में बढ़ कर 6,22,385 करोड़ रुपये पर पहुंच जाने की संभावना है, जो 2015–16 में 5,51,963 करोड़ रुपये था। इसमें 12.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है। वास्तव में, आधार वर्ष 2011–12 के संदर्भ में स्थिर मूल्यों पर 2016–17 में, अग्रिम अनुमानों के अनुसार दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 8.26 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी 7.1 प्रतिशत रहा है। राष्ट्रीय स्तर के जीडीपी में दिल्ली का योगदान 2011–12 के 3.94 प्रतिशत से बढ़ कर 2016–17 में 4.08 प्रतिशत हो गया है, हालांकि देश की कुल आबादी में दिल्ली की हिस्सेदारी मात्र 1.43 प्रतिशत है। दिल्ली के सकल राज्य मूल्य संवर्द्धन (जीएसवीए) में तृतीयक क्षेत्र का योगदान वर्तमान मूल्यों पर 82.26 प्रतिशत है, उसके बाद माध्यमिक क्षेत्र का योगदान 14.84 प्रतिशत और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2.90 प्रतिशत है।

16. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 2016–17 में बढ़ कर 3,03,073 रुपये हो जाने की संभावना है, जो 2015–16 में 2,73,618 रुपये थी। इससे पता चलता है कि 2015–16 की तुलना में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में 2016–17 में 10.76 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2015–16 में 94,178 रुपये थी, जो 2016–17 में बढ़ कर 1,03,818 रुपये होने की संभावना है, जिसमें 10.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि अनुमानित है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय से करीब 3 गुना ज्यादा है।

संशोधित अनुमान 2016–17

17. अध्यक्ष जी, हमारा चालू वर्ष का गैर–योजना व्यय बजट में 26,000 करोड़ रुपये अनुमोदित किया गया था। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हम चालू वित्तीय वर्ष में कुल गैर–योजना व्यय 24,700 करोड़ रुपये के स्तर तक सीमित रखने में सफल होंगे। यह उपलब्धि इस तथ्य के बावजूद हासिल होगी कि हमनें उत्तरी और पूर्वी नगर निगम को वेतन खर्चों से आंशिक रूप से निपटने के लिए 400 करोड़ रुपये का आकस्मिक ऋण देना पड़ा। सरकारी धन का इस्तेमाल विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से करते हुए यह कामयाबी हासिल हुई है। योजना परिव्यय जो 20,600 करोड़ रुपये प्रस्तावित और अनुमोदित किया गया था, उसे 2016–17 के संशोधित अनुमानो में घटा कर 16,500 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। 2016–17 में 16,500 करोड़ रुपये का संशोधित योजना परिव्यय 2015–16 के 14,935 करोड़ रुपये के योजना व्यय से 10.5 प्रतिशत अधिक है। चालू वर्ष के लिए हमारा संशोधित अनुमान 41,200 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जबकि बजट अनुमान 46,600 करोड़ रुपये का था। चालू वर्ष के संशोधित अनुमान वर्ष 2015–16 में खर्च की गई 35,196 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में 17.1 प्रतिशत अधिक है।

2016–17 के लिए पूरक अनुदान मांग

18. अध्यक्ष जी, संशोधित अनुमानों के अंतर्गत पूरक अनुदान मांगें 688.73 करोड़ रुपये की हैं, अतः मैं सदन से पूरक मांगों का अनुमोदन करने की विनती करता हूं।

बजट अनुमान 2017–18

19. अध्यक्ष जी, मैं आगामी वित वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2017–18 के बजट अनुमान योजना और गैर–योजना मदों में नहीं होगें बल्कि इस पुरानी पद्धति को छोड़ते हुए हमारी सरकार ने 2017–18 के बजट में दो प्रमुख श्रेणियों – राजस्व और पूंजी फ्रेमवर्क – के अंतर्गत संसाधन आवंटित किए हैं।

20. इसी तरह इस वर्ष का बजट सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही की दृष्टि से एक ऐतिहासिक नवीनता लिए हुए है। वह है – आउटकम बजट। इसका जिक्र मैंने अपने वक्तवय की शुरूआत में भी किया था।

21. हमारी सरकार का मानना है कि – सरकार और नागरिकों के संबंध एक पवित्र कॉन्ट्रैक्ट यानी करार की तरह होते हैं। यह एक ऐसा करार है जो करदाता को उसकी टैक्स की कमाई के बदले में बेहतरीन नतीजे और सामाजिक लाभ उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। इसी तरह आउटकम बजट अब सरकार और इसके विभिन्न विभागों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट यानी करारनामें की तरह होगा। विभाग अपना लक्ष्य तय करेंगे और सरकार उन्हे उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पैसा देगी और हरेक तिमाही में जनता को उससे हुए फायदे की समीक्षा करेगी।

22. मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार का आउटकम बजट 31 मार्च 2017 तक वेब–साईट पर उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा माननीय सदस्यों को भी इसकी प्रति उपलब्ध करा दी जायेगी। यह बजट सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में सुधार के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यहां यह समझना जरूरी है कि यह बजट सबंधी एक अहम सुधार क्यों है।

23. परम्परागत बजट में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय आवंटनों पर ही जोर दिया जाता है और काम–काज का आकलन इन आबंटनों के सिलसिले में हुए खर्च के आधार पर होता है। सिर्फ कुछ ही मामलों में कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप तैयार बुनियादी ढांचे या सेवाओं का उल्लेख बजट में हो पाता है और सरकारी कार्यक्रमों से नागरिक जिन नतीजों या फायदों की आस लगाए बैठे हैं उनका जिक्र होना तो बहुत दूर की बात है। मिसाल के तौर पर परंपरागत बजट में स्कूलों और क्लिनिकों के निर्माण के लिए आबंटित धनराशि का तो जिक्र किया जाता है, मगर यह कभी नहीं बताया जाता कि कितने लोगों को इनसे फायदा मिलने का लक्ष्य रखा गया है।

24. बजट बनाने के इस परंपरागत तरीके की दो खामियां है पहला – इसमें इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि सरकार आखिरकार जनता की गाढ़ी कमाई से आये टैक्स की संरक्षक है। सरकार का काम महज एक खास अवधि के भीतर पैसा खर्च करना मात्र नहीं होना चाहिए, उसको यह भी देखना चाहिए कि लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार से जो उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं वे पूरी भी हों। दूसरा – परंपरागत बजट में जनता के पैसे के खर्च होने की निगरानी का काम सरकार से बाहर तो छोडिये सरकार के अंदर से भी आसान नहीं था। अब तक बजट के सिर्फ ''योजनागत'' हिस्से में ही कार्यक्रमों और भौतिक लक्ष्यों का ब्यौरा दिया जाता रहा है, जबकि ''गैर–योजनागत'' हिस्सा, जो कि बजट के आधे से ज्यादा होता है, उसकी कोई समीक्षा नहीं होती।

25. दिल्ली के वर्ष 2017–18 के आउटकम बजट में इन सब कमियों की ओर ध्यान दिया जायेगा। पिछले कुछ महीनों में प्रत्येक विभाग और एजेंसी ने जबरदस्त कवायद की जिसमें सभी कार्यक्रमों और योजनाओं (राजस्व और पूंजीगत हिस्सों) का जायजा ठोस परिणामों को ध्यान में रखकर लिया गया। यानी कार्यक्रमों के तहत बनाए गये बुनियादी ढांचे या उपलब्ध करायी गयी सेवाओं और नतीजों को ध्यान में रख कर यह विचार किया गया कि दिल्लीवासियों को इस खर्च से अल्पावधि में क्या फायदा होने जा रहा है। निष्पादन और परिणामों के संकेतकों का एक ऐसा सैट तैयार कर लिया गया है जिसके आधार पर नतीजों का मापन किया जा सकता है। 2016–17 को आधार वर्ष मानकर बुनियादी मानदंड तय कर दिये हैं और 2017–18 के लक्ष्य भी निर्धारित किये गये हैं। इस बात पर खास ध्यान दिया गया है कि तय किये गये संकेतक विशिष्ट हों, मापन योग्य हों और इसी तरह की संस्थाओं तथा कार्यक्रमों, जैसे अस्पताल, कॉलेज, पेंशन योजनाओं आदि से तुलना करने योग्य हों।

इसे कुछ उदहारणों से समझना आसान होगा –

- हम किसी अस्पताल में 10 करोड़ रूपये खर्च करके एक स्केनिंग मशीन लगाते हैं। अब हमारे रिकार्ड में अगर 10 करोड़ रूपये खर्च हो गये और मशीन आ गई तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। भले ही खरीदने के बाद से अब तक उस मशीन पर एक भी मरीज का टेस्ट न हुआ हो। अब आउटकम बजट में हम हर तिमाही में इस बात का डाटा इक्टठा करेंगे कि कितने लोग उस मशीन से लाभान्वित हुए।

- इसी तरह मान लिजिए हम प्रगति मैदान के पास 54 करोड़ रूपये खर्च करके स्काई वॉक बना रहे हैं। अब इस बजट में इस स्काई वॉक का इस्तेमाल कितने लोग करेंगे इसका लक्ष्य पहले से निर्धारित है और स्काई वॉक बनने के बाद हर तिमाही में इसका आंकलन होगा।

- इसी तरह शिक्षा में लगभग 283 करोड़ रूपये में जौनापुर में विश्वस्तरीय कौशल विकास केन्द्र बनाने की योजना है। सामान्य बजट में राशि खर्च होने के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट से ही संतुष्टि मान ली जाती थी लेकिन अब आउटकम बजट में शिक्षा विभाग को सरकार को यह बताना होगा कि इनसे कितने बच्चों को ट्रेनिंग मिली और उनमें से कितनो को नौकरी मिली और कितनो ने अपना कोई रोजगार शुरू किया।

26. दिल्ली की सरकार ने इस काम को अंजाम दिया है उससे वह भारत में ऐसा करने वाली पहली सरकार बन गयी है। आने वाले महीनों में बड़े पैमाने पर जो आंकड़े आएंगे, उनके लिए सूचना टेक्नोलाजी पर आधारित एक 'एप' यानी एप्लिकेशन का विकास किया जाएगा। यह एप्लिकेशन विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये इनपुट या आंकड़ों से त्रैमासिक आधार पर सरकार के तमाम वायदों पर नज़र रख सकेगा और कुछ मामलों में तो यह स्वतंत्र सर्वेक्षणों के आधार पर भी ऐसा करेगा। हमें आशा है कि इससे भारत में किसी भी सरकार के कार्यनिष्पादन के प्रबंधन के लिए पूरी तरह से नये मानदंड तैयार होंगे।

27. मैं दिल्ली सरकार के तमाम कर्मचारियों और योजना विभाग को इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए खास तौर पर बधाई देता हूं। मुझे इस बात का भी अहसास है कि इतनी बड़ी कवायद का यह पहला साल होने की वजह से इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इसमें लगातार सुधार किया जाए।

28. मुझे पक्का यकीन है कि इस कवायद से सभी संबद्धपक्षों को भरपूर फायदा होगा। मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी इसका इस्तेमाल अपनी सभी गतिविधियों के लगातार आकलन के लिए करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि समय पर सुधार भी होता रहे। क्रियान्वयन के स्तर पर कार्यक्रम अधिकारियों को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे उन्हें अपनी सफलताओं के साथ–साथ चुनौतियों को पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत करने का शानदार मौका मिल जाएगा। मगर इस कवायद का सबसे बड़ा फायदा दिल्ली के नागरिकों को होगा। पूरी पारदर्शिता होने के कारण वे जान सकेंगे कि उनकी पसीने की कमाई किस तरह से खर्च की जा रही है। आउटकम बजट नागरिकों और उनकी निर्वाचित सरकार के बीच करार को अंजाम देने वाली प्रणाली बन जाएगा और इस तरह सरकार और उसके विभागों को भी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

29. मुझे यह एलान करते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि आउटकम बजट को अमल में लाने के लिए योजना विभाग में निगरानी एवं मूल्यांकन इकाई (Monitoring & Evaluation Unit) को मजबूत बनाया जा रहा है। यह इकाई दिल्ली सरकार के अंतर्गत निगरानी और मूल्यांकन के आधुनिक तरीकों तथा तकनीकों के कारगर इस्तेमाल के लिए रोड़मैप उपलब्ध कराएगी। इससे नीतियों के निर्माण में सुधार आएगा और सार्वजनिक सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंचाई जा सकेंगी। आउटकम बजट को दिशानिर्देश देने के अलावा इससे दिल्ली सरकार को स्वतंत्र रूप से सर्वेक्षण और मूल्यांकन कराने, आंकड़ों के विश्लेषण यानी डेटा एनालिसिस और सरकार के विशाल डेटाबेस का जायजा लने में भी मदद मिलेगी।

30. अध्यक्ष जी, वर्ष 2017–18 के लिए कुल बजट अनुमान 48,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें 29,500 करोड़ रुपये प्रशासनिक व्यय, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण, भारत सरकार को ब्याज और मूलधन की अदायगी, परिवहन, पानी और बिजली सब्सिडी आदि के लिए हैं और 18,500 करोड़ रुपये विभिन्न कार्यक्रमों, स्कीमों और पूंजी परियोजनाओं आदि से संबंधित हैं। प्रस्तावित 48,000 करोड़ के बजट के लिए धन की व्यवस्था में 38,700 करोड़ रुपये कर राजस्व से, 800 करोड़ रुपये गैर–कर राजस्व से, 400 करोड़ रुपये पूंजी प्राप्तियों से, 2856 करोड़ रुपये लघु बचत ऋण से, 1500 करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित योजनाओं से, 413 करोड़

रुपये सामान्य केंद्रीय सहायता से, 325 करोड़ रुपये केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से और 478 करोड़ रुपये भारत सरकार से अन्य प्राप्तियों और बाकी राशि प्रारंभिक शेष से जुटाने का प्रस्ताव है।

स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता

31. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा 2017–18 में स्थानीय निकायों को 7571 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है, जो कुल बजट का 15.8 प्रतिशत है और वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमान में दिए गए धन से 14.9 प्रतिशत अधिक है। इसके अतिरिक्त उत्तरी और पूर्वी नगरनिगमों की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए हमने 2015–16 और 2016–17 में निगमों के अनुदानों से बकाया ऋण के मूलधन और ब्याज की वसूली नहीं की है।

32. 2017–18 में स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता में 3343 करोड़ रुपये कर वसूली में हिस्सेदारी, 1810 करोड़ रुपये स्टांप और पंजीकरण शुल्क और एकबारगी पार्किंग शुल्क में हिस्सेदारी से सम्बद्ध है और 700 करोड़ रूपये उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को वेज एडं मीन्स के अग्रिम के रूप में है। शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसे क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर अमल करने के लिए हम इस वित्तीय वर्ष में 1718 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करते हैं।

33. हमारी सरकार नगर निगमों को हरसंभव सहायता देने के प्रति वचनबद्ध है। हम नगर निगमों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं, ताकि उन्हें स्वयं के संसाधन बढ़ाने और निरंतर बढ़ते खर्चों पर युक्तिसंगत नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित किया जा सके। मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से नगर निगमों से अपील करता हूं कि वे अपनी कार्य प्रणाली को सुचारू बनाएं ताकि नगर प्रबंधन में कोई आर्थिक संकट न आए और इस महान शहर के लोगों को कोई कठिनाई न उठानी पड़े।

34. अध्यक्ष जी अब मैं 2017–18 के बजट में प्रस्तावित प्रमुख विकास उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा देना चाहूंगा। इन सभी कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा सम्मानित सदन में प्रस्तुत किए गए बजट दस्तावेज में दिया गया है।

शिक्षा

35. अध्यक्ष जी, सरकार के लिए शिक्षा सबसे अधिक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। हमने पिछले दो वर्षों में नए स्कूल बनवाने, नए क्लासरूम बनवाने, खेल के मैदानों, स्वच्छ शौचालय सुविधाओं आदि के निर्माण के रूप में व्यापक ढांचागत सुविधाएं कायम की हैं। इस साल 24 नए स्कूल शुरू हो रहे हैं। 8000 नए कमरों का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसके अलावा 10,000 नए कमरे आगामी वित वर्ष में बनाने का काम शुरू कर लिया जायेगा। हमारी कोशिश है कि दूसरी पारी में चलने वाले अधिकतर स्कूलों को जहां तक संभव हो सके पहली पारी में लाया जा सके। वर्ष 2017–18 के लिए हमने इन तमाम सुविधाओं को इस्तेमाल करते हुए सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देने पर ध्यान दिया है।

36. क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) को पुनर्गठन करने का फैसला किया है। इसके अलावा हमने दिल्ली में दो नये जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) खोलने का फैसला किया है।

37. सरकार ने 2017–18 में 156 सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा से पहले की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है और इसके लिए इन स्कूलों में बुनियादी ढांचे व सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है।

38. एक महत्वपूर्ण कदम हमने बच्चों को पूर्व–प्राथमिक शिक्षा यानी प्री स्कूल लर्निगं उपलब्ध कराने के लिए उठाया है। सरकार की योजना पूरी दिल्ली में सभी वर्ग के बच्चों को बेहतरीन प्री स्कूल लर्निंग उपलब्ध कराने के लिए अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग सेन्टर खोलने की है। यह अपने आप में विश्वस्तरीय सेन्टर होंगे जहां 2 से 6 साल के हर बच्चे को आधुनिक एवं आर्कषक सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी। और उनकी लर्निंग एबिलिटिस पर औपचारिक स्कूली शिक्षा शुरू करने से पहले ही काम किया जायेगा। कई अंतर्राष्ट्रीय अध्यननों में यह बात निकल कर आयी है कि अगर बच्चे के अंदर 2 से 6 साल की उम्र में लर्निंग एबिलिटीज यानी सीखने की योग्यता विकसित करने पर काम कर लिया जाए तो बच्चे की पढ़ाई और उसके जीवन का स्तर बेहतरीन रहता है। इसके पायलट के रूप में 10 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर शुरू करने का काम अम्बेडकर विश्वविद्यालय को सोंपा गया है। अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अर्ली चाइल्डहुड विभाग को इसके उपयुक्त अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण के लिए 4 करोड़ रूपये की राशि प्रदान की गयी है।

39. नर्सरी से लेकर पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए क्लास में ही विशेष लाइब्रेरी बनाने की योजना है। ऐसी लाइब्रेरी पहली बार सरकारी स्कूलों में बनाई जायेंगी। इससे बच्चों के लिए कहानियों की आकर्षक किताबें कक्षा में ही रख दी जाएंगी। इससे उनमें पढ़ने की आदत का विकास होगा, कुछ नया करने की भावना जगेगी और वे कहानी पढ़ने और सुनाने में भी दिलचस्पी लेंगे। इसके लिए 17 करोड़ रूपये की राशि बजट में अलग से रखी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 400 नई लाइब्रेरी छठी से दसवीं कक्षा के लिए बनाई जा रही हैं। इसमें इन बच्चों की उम्र और रूचि के हिसाब से रोमांचक कहानियों, कविताओं आदि की प्रसिद्ध पुस्तके उपलब्ध करायी जायेंगी ताकि बच्चों में पढ़ने की रूचि और बढ़ाई जा सके। इन लाइब्रेरीज को बनाने और पुस्तकें लाने पर 100 करोड़ रूपये का अनुमानित खर्च रखा गया है।

40. हमारी सरकार ने 2017–18 में पांच स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की योजना बनायी है। ये विद्यालय रोहिणी सेक्टर 17, मदनपुर खादर फेज–दो, खिचड़ीपुर, सैक्टर 22 द्वारका और कालकाजी में स्कूलों की नवनिर्मित इमारतों में खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा और प्री–स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्तर की कक्षाएं होंगी। इनमें कला, विज्ञान और

वाणिज्य वर्ग के लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं और प्रयोगशालाएं होंगी ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिले। 2017–18 से 142 स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी स्तर पर वाणिज्य विषय की पढ़ाई शुरू की जाएगी।

41. 2017–18 में यूनीफॉर्म सब्सिडी को संशोधित किया जाएगा और सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को इससे फायदा होगा। इसके लिए मैं 2017–18 के बजट में विद्यार्थियों के लिए सब्सिडी की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। नर्सरी से पांचवी कक्षा तक के लिए यह दर 500 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये की जा रही है। छठी से आठवीं तक के लिए यह 700 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये और नौवीं से 12वीं तक के लिए 900 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

42. मध्याह्न भोजन योजना, पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए केन्द्र की शतप्रतिशत मदद से चलाई जा रही योजना है। केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान सहायता से स्कूलों में बच्चों को दोपहर में दिये जाने वाले भोजन में वांछित स्तर की कैलोरी और गुणवत्ता युक्त पोषण सुनिश्चित करना संभव नहीं है। इसलिए हमारी सरकार ने अपने संसाधनों से हर विद्यार्थी को केला/उबला अंडा देकर भोजन की पौष्टिकता के स्तर को सुधारने का फैसला किया है। बालिका विद्यालयों की नौवीं से बारहवीं तक की सभी छात्राओं को भी मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में लाकर इसका विस्तार करने का भी प्रस्ताव है। इसके लिए राज्य सरकार 55 करोड़ रूपये अतिरिक्त देगी।

43. अभी सरकारी स्कूल की लैबस में अधिकतम 11 कम्पयूटर होते हैं अगले वित वर्ष में सभी लैबस में 6 से 7 कम्पयूटर बढायें जायेंगे। साथ ही दो शिफ्ट वाले स्कूलों में अब दो–दो कम्पयूटर लैबस चलेंगी। 2,000 से अधिक बच्चों वाले स्कूल में कम्पयूटर लैबस की संख्या बढाई जायेगी। इसके लिए बजट में 182 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।

44. दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में कॉमर्स स्ट्रीम शुरू की जायेगी। सभी स्कूलों में पंजाबी और उर्दू के क्लब बनाये जायेंगे। जिसमें बच्चों को पंजाबी और उर्दू पढने के अलावा इन भाषाओं की साहित्य कला आदि गतिविधियों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसी तरह सभी स्कूलों में आर्ट व म्यूजिक की पढ़ाई शुरू की जायेगी। साथ ही पहली बार हर स्कूल में एक डांस टीचर रखने की एक योजना भी बनाई गई है ताकि बच्चे परमपरागत भारतीय नृत्य कलाओं की शिक्षा ले सकें। इसके लिए शिक्षा विभाग में अलग से Extra Curriculam Activity Department शुरू किया जायेगा।

45. शिक्षकों के लिए दिल्ली सरकार ने कई योजनाएं पिछले 2 वर्षों में लागू की है जिससे उन्हें अपने काम को गरिमा से पूरा करने में मदद मिल सके। आगामी वर्ष में सरकार सभी स्कूलों में शिक्षकों के लिए बने स्टाफ रूम को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करेगी ताकि वहां शिक्षकों को अलग से वर्क–स्टेशन मिल सके, बैठने की अलग से जगह मिल सके, लाकर्स मिल सकें और उनके लिए चाय, काफी, पानी आदि की मशीने भी उपलब्ध हो सकें।

46. इस वर्ष सभी शिक्षकों को एक–एक कम्पयूटर टेबलेट्स दिये जाने की योजना है ताकि सभी शिक्षक अपने छात्रों का डाटा या अन्य जानकारी इसमें रख सकें। इससे शिक्षकों का कागजी कार्यवाही पर जाया होने वाला समय बच सकेगा।

47. अंबेडकर विश्वविद्यालय फिलहाल कश्मीरी गेट और कर्मपुरा स्थित अपने परिसरों से कार्य कर रहा है और 2100 विद्यार्थी इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के चार नये परिसर 2022 तक धीरपुर, रोहिणी, कराला और लोधी रोड में खोले जाएंगे, जिससे इसमें पढ़ने वालों की संख्या 2100 से बढ़कर 10000 हो जाने का अनुमान है। लोधी रोड़ में अम्बेडकर विश्वविद्यालय के तहत एक बेहद हाई क्वालिटी टीचर ट्रेंनिग इंस्टीटयूट शुरू किया जा रहा है। गुरु गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पूर्वी दिल्ली कैंपस का काम सूरजमल विहार में 271 करोड़ रुपये की लागत से जल्द शुरू हो जाएगा। रोहिणी में 2000 विद्यार्थियों की क्षमता वाला शहीद सुखदेव कॉलेज जून 2017 तक बन कर तैयार हो जाएगा।

48. अध्यक्ष जी, एनएसआईटी, डीटीयू और आईआईआईटी के विस्तार की परियोजनाएं बनाई गयी हैं ताकि अधिक संख्या में विद्यार्थियों को सीटें दी जा सकें। पूर्वी दिल्ली में अगले वर्ष शुरू हो रहे डीटीयू के नए कैंपस की क्षमता 2000 विद्यार्थियों की है। वर्तमान कैंपस के विस्तार से 4000 और विद्यार्थी इसमें दाखिला ले सकेंगे जिससे इसकी क्षमता बढ़कर 12000 हो जाएगी। नेताजी सुभाष इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (एनएसआईटी) में दाखिला लेने वालों की संख्या 4000 से बढ़कर 10000 हो जाएगी। आईआईआईटी दिल्ली का नया परिसर बनने से 1400 और विद्यार्थी इसमें दाखिला ले पाएंगे। जी.बी. पंत इंजीनियरी कालेज के नये परिसर की भी योजना बनायी गयी है जिससे इसकी क्षमता वर्तमान 3000 से बढ़कर 7000 हो जाएगी। इंदिरा गांधी महिला टेक्निकल यूनीवर्सिटी का स्थायी कैंपस डेरा मांडी गांव में 50 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा।

49. भारत के पहले औषधि शिक्षा विश्वविद्यालय –दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (DPSRU) के अंतर्गत पहला कालेज दिल्ली इंस्टीटयूट आफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च के रूप में शुरू कर दिया है। इसमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 160 सीटें बढ़ा दी गयी हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्पोर्ट्स मेडिसिन पाठ्यक्रम 2017–18 के शैक्षिक सत्र से शुरू हो जाएगा।

50. खेल–कूद को बढ़ावा देने और खेलों के लिए कोचिंग की सुविधाएं मजबूत करने के लिए खेलों के बुनियादी ढांचे के विस्तार का प्रस्ताव है ताकि अच्छी खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आएं। सरकार ने खिलाड़ियों के लिए तमाम आधुनिक सुविधाओं से युक्त दो बहुमंजिला होस्टल बनाने की योजना बनायी है इनमें 2350 खिलाडी रह सकेंगे। सरकार ने कैर गांव में खेल सुविधाएं विकसित करने का फैसला किया है। नजफगढ़ इलाके में समसपुर खालसा और वसंतकुंज में शिक्षा विभाग द्वारा हाल में अधिगृहीत कथूरिया पब्लिक स्कूल में आवासीय खेलकूद स्कूल खोलने का भी फैसला किया गया है। खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और खेल प्रशिक्षकों के 110 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे जो कि वर्तमान में 19 हैं।

51. शिक्षा क्षेत्र हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं 2017–18 में शिक्षा पर कुल 11300 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 10186 करोड़ रुपये का राजस्व बजट और 1114 करोड़ रुपये का पूंजी बजट शामिल है। विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 3525 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। दिल्ली में कुल बजट में से शिक्षा क्षेत्र के लिए करीब 24 प्रतिशत का आबंटन देश के तमाम राज्यों में सर्वाधिक है। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार के हमारे संकल्प का पता चलता है।

स्वास्थ्य

52. शिक्षा के साथ–साथ स्वास्थ्य भी दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार चाहती है कि दिल्ली का हर नागरिक अपने या किसी परिजन के बीमार होने की स्थिति में असुरक्षित महसूस न करे। उसके अंदर अस्पताल के बिल या सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर डर न आये। इसलिए पिछले दो वर्ष में सरकार ने त्रि–स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापित करने पर काम किया है। अगले वित वर्ष में भी सरकार इसी त्रि–स्तरीय व्यवस्था को मजबूत करने पर काम करेगी।

53. पहले स्तर पर मौहल्ला क्लीनिक हैं जहां एक आम आदमी सामान्य बीमारी के लिए योग्य डाक्टर से अपना ईलाज कराने के लिए जा सके। इन मौहल्ला क्लीनिक्स में योग्य चिकित्सक की सेवायें, दवाईयां और टेस्ट इत्यादि मुफ्त उपलब्ध कराये जाते हैं। 110 ऐसी मौहल्ला क्लीनिक दिल्ली में शुरू हो चुकी हैं और उम्मीद है कि इस वित वर्ष के अंत तक इनकी संख्या 150 से उपर हो जायेगी। अगले वित वर्ष में हम 1000 मौहल्ला क्लीनिक पूरी दिल्ली में बनाने का लक्ष्य हासिल कर लेगें। इस पर तेजी से काम चल रहा है।

54. दूसरे स्तर पर पॉलीक्लीनिक हैं जहां हर एक बीमारी के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे। दवाईयां और टैस्ट फ्री होंगे लेकिन यहां मरीजों को भर्ती नहीं किया जायेगा यानि बेड्स नहीं होगें। ऐसे 23 पालिक्लीनिक शुरू कर दिये गये हैं और अगले वित वर्ष में इनकी संख्या 150 कर दी जायेगी।

55. तीसरे स्तर पर अस्पताल हैं जहां दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों को मिला कर अभी 10,000 बेड्स हैं इन्हे बढ़ाकर 20,000 बेड्स किये जाने पर काम चल रहा है। अगले 18 महीनों मे यह काम पूरा होने की उम्मीद हैं । इसके साथ ही बुराड़ी, अम्बेडकर नगर व द्वारका में 3 अस्पताल निमार्णाधीन हैं और सरिता विहार, नांगलोइ, मादीपुर व सिरसपुर में 4 अस्पताल बनाये जाने हैं। इन 7 नए अस्पतालों में 5000 नए बेड्स होंगे इस प्रकार पूरी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में बेड्स की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 के लक्ष्य पर अगले वित वर्ष में तेजी से काम होगा।

56. सरकार सभी नागरिकों का हेल्थ कार्ड बनवाने और उन्हे हेल्थ बीमा देने की योजना पर भी काम कर रही है। इन योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

57. हमारी सरकार ने ऐसे गुड स्मारिटन्स या मददगारों को सम्मानित करने का फैसला किया है, जो सड़क दुर्घटना के मामले में पीड़ित व्यक्ति का जीवन बचाने और उपचार के लिए उसे अस्पताल ले जाने में सहायता करते हैं। ऐसे मददगार व्यक्ति को सरकार की ओर से पुरस्कार स्वरूप 2000 रुपये नकद एवं प्रशंसा पत्र दिया जाएगा।

58. दिल्ली सरकार के अस्पतालों में किशोरों के लिए 5 नशामुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र में 5 बिस्तरों की व्यवस्था होगी।

59. दिल्ली सरकार के 5 अस्पतालों (लोक नायक, गुरू तेग बहादुर, बाबा साहेब अम्बेडकर, दीन दयाल उपाध्याय और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल) की फार्मेसियों को आउटसोर्स किया जाएगा और इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के बाहर एक निशुल्क जेनेरिक फार्मेसी – जनऔषधि स्थापित की जाएगी।

60. दिल्ली सरकार के अस्पतालों के जरिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्राप्त करने वाले नागरिकों के लिए एमआरआई/सीटी स्कैन जांच पहले ही निःशुल्क की जा चुकी है। सरकारी–निजी–भागीदारी के जरिए प्रयोगशाला सुविधाओं और डायग्नोस्टिक्स/टेली रेडियोलोजी सेवाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। अगले वर्ष में इन सभी सुविधाओं के लिए 15 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

61. हमारी सरकार ने निजी क्षेत्र के 41 अस्पतालों के साथ भागीदारी में 30 महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक शल्य चिकित्साओं में गुणवत्तापूर्ण उपचार की व्यवस्था करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके अंतर्गत ऐसे रोगियों को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जाएगा, जिनका दिल्ली सरकार के अस्पताल में इलाज चल रहा हो और जिन्हें अपेक्षित उपचार के लिए लंबी अवधि का इंतजार करना पड़ रहा हो। इस तरह सरकारी अस्पतालों द्वारा रेफर किए गए चिंताजनक रोगियों के पूर्ण उपचार और देखभाल के लिए दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पतालों को सीजीएचएस की दरों से उपचार का खर्च अदा करेगी।

62. 2017–18 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मैं कुल 5736 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 5048 करोड़ रुपये का राजस्व बजट और 688 करोड़ रुपये का पूंजी बजट शामिल है। विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 2627 करोड़ रुपये निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

सार्वजनिक परिवहन

63. अध्यक्ष जी, वर्तमान में डीटीसी और क्लस्टर सेवा के अंतर्गत 5815 बसें दिल्ली में प्रचालित हैं, जो हर रोज करीब 46 लाख यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाती हैं। 2017–18 के दौरान क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत 736 और बसें शामिल हो रही हैं।

64. बस डिपो/टर्मिनलों के लिए जगह के अभाव के कारण बसों के बेड़े में बढ़ोतरी करना एक बड़ी चुनौती थी। हमारी सरकार ने इस मामले को प्राथमिकता दी और 11 नए बस डिपो बनाने का निर्णय किया। ढिचाउ कलां–II, द्वारका सेक्टर 22, बवाना सेक्टर 1, बवाना सेक्टर 5, रेवला खानपुर, खरखड़ी नाहर, रोहिणी फेज–5 में रानीखेड़ा–1, रानीखेड़ा–2 और रानीखेड़ा–3, नरेला और पूर्वी विनोद नगर में बनाए जा रहे नए बस डिपो का निर्माण कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। मैं 2017–18 के दौरान बस टर्मिनलों और डिपो के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूॅं।

65. यात्रियों को अंतिम गंतव्य तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने लैटर ऑफ इंटेंट स्कीम का अनुमोदन कर दिया है और फलस्वरूप इस वर्ष 10 हजार नए ऑटो परमिट जारी किए जाने की संभावना है।

66. हमारी सरकार बसों के प्रचालन में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रति वचनबद्ध है, जिसके लिए स्टेज कैरिज बसों में इलेक्ट्रोनिक टिकट मशीन शुरू की गई है। अब सभी क्लस्टर बसों में इलेक्ट्रोनिक टिकट मशीनें लगाई गई हैं। डीटीसी की भी सभी बसों में इलेक्ट्रोनिक टिकट मशीनें लगाने का प्रस्ताव है।

67. डीएमआरसी का मौजूदा नेटवर्क 189 किलोमीटर का है। डीएमआरसी के तीसरे चरण के पूरा होने पर यह बढ़कर लगभग 325 किलोमीटर हो जाएगा। सरकार ने मेट्रो के चौथे चरण का अनुमोदन कर दिया है, जिसमें 6 कॉरीडोर बनाए जाएंगे और इनकी लंबाई 104 किलोमीटर होगी। मेट्रो के चौथे चरण का काम वर्ष 2017–18 में शुरू किया जाएगा और इसे दिसंबर, 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मेट्रो यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए 582 अतिरिक्त डिब्बे खरीदने का प्रस्ताव है। मैं 2017–18 में डीएमआरसी के लिए 1156 करोड़ रूपये का प्रस्ताव करता हूॅं।

सड़क ढ़ांचा

68. आउटर रिंग रोड पर विकासपुरी से वजीराबाद तक सभी एलिवेटिड कॉरीडोरों को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इससे आउटर रिंग रोड पर वाहनों की भीड़ कम करने में मदद मिली है। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से वजीराबाद चौक तक नाले के एक तरफ समानांतर सड़क का निर्माण करने से भलस्वा, मुकुंदपुर, बुराड़ी, संगम विहार, जगतपुर, वजीराबाद और अन्य निकटवर्ती कालोनियों के स्थानीय लोगों को सुविधा प्राप्त होगी।

69. मथुरा रोड पर आश्रम चौक के निकट अंडरपास के निर्माण का कार्य 2017—18 में शुरू किया जाएगा। इस अंडरपास का निर्माण पूरा होने के बाद नीला गुंबद रोटरी से बदरपुर बार्डर की ओर जाने वाले वाहनों को बिना किसी बाधा के निकलने में मदद मिलेगी और आश्रम चौक पर भीड़भाड़ कम की जा सकेगी।

70. अध्यक्ष जी, मैंने पिछले बजट में आईएसबीटी आनंदविहार से पीरागढ़ी तक ईस्ट वेस्ट कॉरीडोर और वजीराबाद से एयरपोर्ट तक नार्थ साउथ कॉरीडोर बनाने की घोषणा की थी। इन दोनों परियोजनाओं के लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए गए हैं और फिजीबिलीटी स्टडी का कार्य प्रगति पर है।

71. आईटीओ पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिकंदरा रोड, मथुरा रोड, तिलक मार्ग और बहादुरशाह जफर मार्ग पर डब्ल्यू प्वाइंट और हंस भवन के निकट स्काईवॉक और एफओबी के निर्माण का प्रस्ताव है। इस पर 54.84 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है।

72. सराय कालेखां से मयूर विहार तक बारापुला नाला फेज़ 3 के अंतर्गत एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य इस वर्ष पूरा हो जाएगा। मैं इस परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं। महिपालपुर और एयरपोर्ट रोड के बीच नए फ्लाइओवर/अंडरपास के निर्माण का काम भी वर्ष 2017–18 में शुरू किया जाएगा।

73. मैं 2017–18 में सड़क ढ़ांचे सहित सार्वजनिक परिवहन के लिए कुल 5506 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूं। इसमें 3512 करोड़ रूपये का राजस्व बजट और 1994 करोड़ रूपये का पूंजी बजट शामिल है। परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 3056 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

74. अध्यक्ष जी, हम समाज के निर्धन और उपेक्षित वर्गों, विधवा एवं बेसहारा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, विधवा एवं बेसहारा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। करीब 6.3 लाख व्यक्तियों को यह लाभ दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत दी जाने वाली पेंशन में 1000 रुपये की वृद्धि पहले ही की जा चुकी है। स्कीमों का लाभ उठाने के लिए आय सीमा की पात्रता 60,000 रुपये वार्षिक से बढ़ा कर 1,00,000 लाख रुपये वार्षिक की जा चुकी है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत बजट आवंटन 2017–18 में बढ़ाकर 1,595 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जबकि 2016–17 के संशोधित अनुमानों में इस मद के लिए 1,137 करोड़ रुपये दिए गए थे।

75. हमारी सरकार 2017–18 में ''वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग'' की स्थापना करेगी। यह संगठन दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और संरक्षा संबंधी मुद्दों की देखरेख करेगा।

76. सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी चला रही है। इनमें स्टेशनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की अदायगी आदि कार्यक्रम शामिल हैं। 2017–18 में एस.सी.एस.पी. कम्पोनेंट (789 बजट हैड) के अंतर्गत 900 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जो 2016–17 के संशोधित अनुमान की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक हैं।

77. 2017–18 में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए मैं कुल 3467 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव करता हूं। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 3081 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

जलापूर्ति और स्वच्छता

78. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार इस बात का महत्व समझती है कि जल मानव का अधिकार है और यह कोई वस्तु नहीं है। हमारी सरकार का संकल्प है कि 2017 के अंत तक अधिकृत और अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले सभी परिवारों को पाइपलाइन के जरिए पेयजल प्रदान किया जाए। दिल्ली जल बोर्ड 1200 अनाधिकृत कालोनियों में पेयजल सुविधा प्रदान कर रहा है और सभी झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में पब्लिक वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए जलापूर्ति की जाती है। और इस वर्ष दिल्ली के सभी जे जे कल्सटर्स में पानी की लाईन डालने का लक्ष्य रखा गया है।

79. हम प्रत्येक परिवार को हर महीने 20 किलोलीटर निःशुल्क जल आपूर्ति करने का कार्यक्रम जारी रखेंगे। मैं गर्व के साथ सम्मानित सदन को यह बताना चाहता हूं कि लगभग 12.57 लाख से ज्यादा उपभोक्तओं के जीरो वाटर्स बिल आये हैं। चाहे वो चिराग दिल्ली जैसे सैकडों साल पुराने गांव हों या किराड़ी की अनाधिकृत कालोनी। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को पहली बार घर के अंदर पानी सप्लाई हुआ है। यहां यह बताना भी जरूरी है कि 12.57 लाख से ज्यादा

उपभोक्तओं को जीरो वाटर बिल देने के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड ने 178 करोड़ का अतिरिक्त रिवेन्यू कमा कर दिखाया है।

80. 2017–18 का साल दो मायनो में महत्वपूर्ण है। एक ओर हम सभी अनाधिकृत कालोनियों और जे.जे. कलस्टर सहित समूची दिल्ली में पानी की लाईन बिछाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वहीं वाटर क्वालिटी को लेकर एक बडी शुरूआत करने जा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की प्रयोगशालाओं के मार्डनाईजेशन की शुरूआत जो हमने पिछले वर्ष शुरू की थी उसे जारी रखा जाएगा।

81. पिछला साल वाटर इंफ्रास्टरकचर के मामले में ऐतिहासिक रहा है। हमारी सरकार आने के बाद 309 अनाधिकृत कालोनियों में पानी की सप्लाई शुरू की गई जो पूरे देश में एक रिकार्ड है। वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए वर्ष के दौरान दिल्ली के विभिन्न जिलों में 70 किलोमीटर लंबी पुरानी/अवरुद्ध/क्षतिग्रस्त/रिसने वाली पाइपलाइन को बदला गया। दिल्ली जल बोर्ड ने 700 टैंकरों के मौजूदा बेड़े में 250 नए स्टेनलेस स्टील के वाटर टैंकर जोड़े हैं। पानी की कमी वाले क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थलों पर 29 वाटर एटीएम और 15 ई–प्याऊ स्थापित किए हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी निधि से सार्वजनिक स्थलों पर अधिक संख्या में ई–प्याऊ लगाने की योजना बनाई है।

82. दिल्ली जल बोर्ड शहर के विभिन्न भागों में चौबीसों घंटे और सातों दिन जलापूर्ति का सपना पूरा करने की दिशा में अथक प्रयास कर रहा है। नवजीवन विहार और गीतांजलि एन्क्लेव में इसकी शुरूआत की गई है। इन इलाकों में मार्च 2017 से चौबीसों घंटे जलापूर्ति की जाएगी। इससे पहले, इन क्षेत्रों में निर्धारित समय पर पानी की आपूर्ति की जा रही थी। 24 घंटे और सातों दिन जलापूर्ति से न केवल पानी की दिन–रात उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, बल्कि इस बात की भी गारंटी दी जाएगी कि टैप से सीधे स्वच्छ पेयजल मिले। टैप से सीधे पानी पीने की स्कीम इस वर्ष कुछ कालोनियों में शुरू की जाएगी, जिसका बाद में समूची दिल्ली में विस्तार किया जाएगा।

83. 24X7 आपूर्ति प्रणाली के अंतर्गत अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के बारे में एक विस्तृत योजना बनाई जा रही है। मौजूदा नेटवर्कों को नया रूप दिया जा रहा है। ''वॉक द लाइन'' नाम के नवीन कार्यक्रम के जरिए आपूर्ति प्रणाली का समूचे शहर में मूल्यांकन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से नेटवर्क की खामियों के बारे में व्यापक डेटाबेस मिलेगा।

84. पानी के लिए दिल्ली अन्य राज्यों पर निर्भर है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बरसात एवं बाढ़ का पानी रोककर दिल्ली का वाटर प्रोडक्शन बढ़ाने का एक अनूथा प्रयास दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। रेन वाटर हारवेस्टिंग के माध्यम से वाटर प्रोडक्शन बढ़ाने का काम दिल्ली जल बोर्ड ने बुराड़ी में शुरू किया है। इसी के साथ दिल्ली जल बोर्ड ने पहली दफा शहर के भीतर पानी की मात्रा बढ़ाने के क्षेत्र में अपने प्रयास शुरू किए हैं। पर्यावरण के अनुकूल उपाय अपनाते हुए कुल 20 एमजीडी जल का प्रोडक्शन बढाया जाएगा। 92 नए ट्यूबवेल लगाने और पुराने 100 ट्यूबवेलों के पुनर्विकास, पल्ला में 4 बरसाती कुओं और पुराने पंपों के स्थान पर नए पंप लगाने तथा SCADA की संस्थापना करने जैसे उपायों के जरिए जलापूर्ति में वृद्धि की जा रही है। इसी प्रकार अवरुद्ध बरसाती कुओं को बहाल करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। पुराने तालाबों और बावलियों को पुर्नजीवित करने के लिए भी एकशन प्लान बनाया जायेगा।

85. इसी वर्ष कराला, मंगोलपुरी और मंगोलपुर कलां में भूमिगत जलाशयों को चालू किया जाएगा और मायापुरी, महिपालपुर में यह कार्य शुरू किया गया है। पिछले वर्ष 309 कालोनियों में जलापूर्ति नेटवर्क कायम किया गया। दिल्ली जल बोर्ड के इतिहास में यह एक कीर्तिमान है। इससे सभी 1200 अनधिकृत कालोनियों में व्यापक जलापूर्ति प्रणाली कायम की जा सकी है। ऐसी 200 और कालोनियों को जलापूर्ति नेटवर्क के अंतर्गत लाया जाएगा।

86. कोरोनेशन पिलर के निकट 70 एमजीडी क्षमता के उत्सर्जित जल उपचार संयंत्र का निर्माण कार्य सितंबर 2016 में शुरू किया गया। इसे 30 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है। यह प्लांट आधुनिकतम तकनीक पर आधारित अपनी तरह का देश में सबसे कम लागत में बनने वाला प्लांट है।

87. दिल्ली गेट पर 15 एमजीडी सीवरेज उपचार संयंत्र और यमुना विहार में 25 एमजीडी एसटीपी चालू कर दिए गए हैं। कोरोनेशन पिलर में 315 एमएलडी के बड़े सीवर उपचार संयंत्र का निर्माण कार्य अवार्ड कर दिया गया है और इसे अगले 2 वर्ष में पूरा किया जाएगा। यह संयंत्र तृतीयक गुणवत्ता के अनुसार मल–जल का उपचार करेगा और नाइट्रोजन और फासफोरस हटाने में सक्षम होगा। सभी पुराने मल–जल उपचार संयंत्रों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, ताकि नदी जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए निर्धारित बी.ओ.डी. 10 से कम और एस.एस. 10 पी.पी. एम. से कम मानक के अनुसार उत्सर्जित जल का उपचार किया जा सके।

88. इसी वर्ष सभी मल जल पम्पिंग स्टेशनों को स्वचालित बनाया जाएगा ताकि पम्पिंग का अनुकूलतम इस्तेमाल और टैंक सीवरों में चैनल–फ्लो सुनिश्चित किया जा सके। इससे नालों की गाद हटाने के काम में कमी आएगी।

89. यमुना की सफाई के लिए 3 प्रमुख नालों (नजफगढ़ सप्लीमेंटरी और शाहदरा) पर इंटर सेप्टर सीवर बिछाने की परियोजना शीघ्र पूरी की जाएगी, जिससे इन नालों में बहने वाले 240 एमजीडी मल–जल को ट्रैप किया जाएगा और समुचित उपचार के लिए विभिन्न मल–जल संयंत्रों की तरफ मोड़ा जाएगा।

90. सप्लीमेंटरी नालों को नया रूप देने के लिए कंसल्टेंसी का काम इस्राइल की एक फर्म को दिया गया है। इस वर्ष मुकरबा चौक से वजीराबाद तक 8.5 किलोमीटर के दायरे में प्रायोगिक परियोजना के तौर पर सप्लीमेंटरी ड्रेन की सफाई, अपलिफ्टिंग और विकास का काम शुरू किया जाएगा।

91. मैं 2017–18 के लिए जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए कुल 2108 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 1180 करोड़ रुपये राजस्व बजट और 928 करोड़ रुपये पूंजी बजट से सम्बद्ध हैं।

आवास और शहरी विकास

92. अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार दिल्ली को स्लम फ्री शहर बनाने के लिए कृतसकंल्प है। लेकिन यह काम झुग्गियों को उजाड़ कर नहीं बल्कि झुग्गियों में रह रहे नागरिकों को गरिमापूर्ण जिंदगी के लिए छोटे घर देकर शुरू किया है।

93. पिछले 2 वर्षों के दौरान डयूसिब ने ज्वालापुरी, कीर्तिनगर, पंजाबी बाग, जनपथ, झारखंड भवन और एनएच 24 इत्यादि स्थानों पर बसी विभिन्न झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों से करीब 5000 व्यक्तियों को बापरौला और द्वारका में फ्लैट देकर पुर्नस्थापित किया हैं।

94. इसी प्रकार दिल्ली को खुले शौच से मुक्त शहर बनाने पर भी तेजी से काम शुरू हुआ। मैं इसके लिए डयूसिब की पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होने कई हफ्तों तक रोज़ाना शुबह 3 बजे जा–जा कर ऐसे इलाकों का सर्वे किया जहां लोग खुले में शौच करते हैं और इसके आधार पर दिल्ली को खुले शौच से मुक्त बनाने का प्लान तैयार किया। इस प्लान पर काम करते हुए पूरी दिल्ली में आधुनिक सुविधाओं से युक्त साफ–सुथरे 8000 टायलेटस तैयार हो चुके हैं, 6000 जून 2017 तक तैयार हो जायेंगें और इसके अलावा अगले साल 5000 टायलेटस और बनाये जायेंगे। इस तरह कुल 19000 टायलेटस का निमार्ण कर पूरी दिल्ली को खुले शौच से मुक्त किया जायेगा।

95. अध्यक्ष जी, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि डयूसिब और नाईट शेल्टर की टीम की सक्रियता के कारण दिल्ली में हम ठंड के कारण होने वाली मौत की घटनाओं को रोकने में कामयाब रहे। डयूसिब दिल्ली में बेघर लोगों को शेल्टर प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है। चालू वर्ष के दौरान 266 शेल्टरों में कुल क्षमता बढ़ा कर 21,724 की गई। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत नांगलोई फेज–2, द्वारका सेक्टर–3, रोहिणी सेक्टर–5, गीता कालोनी की निकटवर्ती जे.जे. बस्ती में बेघरों के लिए रैन बसेरे बनाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक रैन बसेरे में पर्याप्त संख्या में कंबल, दरियां, चटाइयां, पेयजल, प्राथमिक उपचार, विद्युत और एमरजेंसी लाइट आदि सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

96. मैं 2017–18 में आवास और शहरी विकास क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 3113 करोड़ रुपये के कुल व्यय का प्रस्ताव करता हूँ, जोकि संशोधित बजट 2016–17 से 21 प्रतिशत अधिक है।

ऊर्जा

97. दिल्ली सरकार ने सितंबर 2016 में सौर नीति को अधिसूचित करके सौर ऊर्जा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जगह की कमी की वजह से दिल्ली में सौर ऊर्जा क्षमता के विकास के लिए इमारतों की छत का उपयोग करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में सोलर फोटोवोल्टैक प्रणालियां स्थापित करके 1000 मेगावाट क्षमता सृजित करने और 2025 तक इसे 2000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ऐसी सभी सरकारी इमारतों के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियां लगाना अनिवार्य कर दिया गया है जिनका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक है। इन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को सौर फोटोवोल्टैक पावर प्लांट लगाने पर 2 रुपया प्रति यूनिट प्रति किलोवाट की दर से बिजली उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन दिया जाएगा।

98. शहरी ठोस कचरे के निपटारे की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने तीन स्थानों – ओखला, गाजीपुर और बवाना में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है जिनकी कुल क्षमता 52 मेगावाट होगी। ओखला में 16 मेगावाट क्षमता का संयंत्र पहले ही काम कर रहा है। यह भारत में ठोस कचरे के प्रबंधन की ऐसी सबसे बड़ी परियोजना है, जिसकी क्षमता रोजना 2000 टन कूड़ा–करकट निपटाने की है।

99. मैं वर्ष 2017–18 में ऊर्जा पर कुल 2194 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव करता हूं। जिसमें 1600 करोड़ रूपये बिजली सब्सिडी के शामिल हैं जिसके तहत पिछले दो साल से दिल्ली के घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर बिजली आधे दाम पर मिल रही है।

पर्यावरण और वन

100. पर्यावरण की समस्याएं नगर और इसमें रहने वालों की खुशहाली के साथ–साथ यहां के जीव–जंतुओं और वनस्पतियों के लिए भी एक खतरा हैं। आबादी में बेतहाशा बढ़ोतरी और तेज आर्थिक विकास से दिल्ली में पर्यावरण के बिगड़ने की समस्या भी उत्पन्न हुई है। हाल ही में पर्यावरण की हालत सुधारने के लिए कई कदम उठाये गये हैं जिनके अंतर्गत पेड़–पौधे लगाने, सभी वाणिज्कि वाहनों में सीएनजी के उपयोग, बैटरी से चलने वाले नये चौपहिया व दुपहिया वाहनों पर सब्सिडी, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक, कूड़े–कचरे का बेहतर प्रबंधन, गंदे पानी का उपचार और सीवेज प्रणाली में सुधार जैसे उपाय शामिल हैं।

101. अध्यक्ष जी, हम प्रदूषण के स्तर की लगातार रीअल टाइम आधार पर निगरानी कर रहे हैं जिसके लिए हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें परिवेशी वायु की गुणवत्ता का आंकलन किया जाता है। इस तरह के केन्द्रों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 26 करने का प्रस्ताव है जिनके माध्यम से वायु में विद्यमान धूल आदि के कणों और गैसों की मात्रा (जैसे पीएम$_{2.5,}$ पीएम$_{10}$, सल्फर डाई ऑक्साइड, नाईट्रोजन डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ओज़ोन, बेंजीन और अमोनिया) के बारे में जानकारी दी जाती है।

102. दिल्ली में प्रदूषण न फैलाने वाले बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के बैटरी चालित वाहनों को अपनाने वालों को सब्सिडी देने की योजना घोषित की थी। वर्ष 2016–17 में 686 ऐसे वाहनों को 1.06 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी। यह सब्सिडी अगले साल भी जारी रहेगी।

103. अध्यक्ष जी, हम दिल्ली को हरी–भरी दिल्ली बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। 2016 के दौरान हमने बड़ा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जिसके अंतर्गत पेड़ों के 8.43 लाख और झाड़ीदार पेड़ों के 11.72 लाख पौधे रोपे गये। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही कि दिल्ली के फोरेस्ट कवर में लगभग 1 प्रतिशत का इजाफा हुआ है इसका मतलब है कि दिल्ली में लगभग 600 एकड़ जमीन पर हरियाली और बढ़ गई है।

104. इसी तरह, दिल्ली के पर्यावरण की दृष्टि से एक नया प्रस्ताव, मैं इस वर्ष सदन में रख रहा हूं जिसका संबंध दिल्ली में अंग्रेजो के इतिहास से है। 1912–13 के आस पास अंग्रेजो ने दिल्ली में विलायती कीकर लगाया था। इसकी वजह से दिल्ली की जमीन के नीचे पानी की काफी समस्या बढ़ी है। सरकार की योजना है कि पूरी दिल्ली से विलायती कीकर को हटाकर यहां अमलतास आदि स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष लगाये जायें और अन्य फल व फूलों के वृक्ष लगाये जायें। दिल्ली को कीकर–फ्री बनाने की इस योजना को इस साल सेंट्रल रिज इलाके से शुरू किया जायेगा। यह एक लम्बी योजना है वर्ष 2017–18 के लिए इस पर खर्च के लिए 50 लाख की राशि प्रस्तावित की गई है।

105. रजोकरी में करीब 6 एकड़ इलाके में पहला वन्य प्राणी बचाव केन्द्र (पक्षी विहार) बनाने का भी प्रस्ताव है जो विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा । गढ़ी मांडू, बेला फार्म, शास्त्री पार्क, इस्सापुर, खड़खड़ी जटमल, अलीपुर और मुखमेलपुर में नये नगरवनों के विकास का प्रस्ताव है ताकि ये स्थानीय लोगों की पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

106. मैं 2017–18 में पर्यावरण और वनों के लिए 106 करोड़ रुपये के कुल खर्च का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 75 करोड़ रुपये का राजस्व बजट और 31 करोड़ रुपये का पूंजी बजट शामिल है। पर्यावरण और वन क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 57 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की जा रही है।

ग्रामीण विकास

107. अध्यक्ष जी, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की सुविधाओं जैसे संपर्क मार्गों, योजक सड़कों, पार्कों, छोटे नालों आदि के निर्माण तथा गांवों के लोगों को आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ''दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड'' विकास संबंधी कार्य करता है। हमारा विचार है कि दिल्ली के शहरी गांवों में भी विकास कार्य उतने ही जरूरी हैं जितने देहाती गांवों में। इसलिए सरकार ने ''दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड'' का दायरा बढ़ाकर रूरल और अर्बन दोनो ही

तरह के गावों को इसमें शामिल करने का फैसला लिया है। इसके लिए बोर्ड को दी जाने वाली राशि को वर्तमान 132 करोड़ रूपये से बढ़ाकर वर्ष 2017—18 में 600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूं। यानि इसमें चार गुने से अधिक बढ़ोतरी की जा रही है। इस राशि का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के सभी गावों को उनकी आबादी के अनुपात में लगभग 2—2 करोड़ रूपये की धनराशि का आबंटन किया जाएगा।

108. अध्यक्ष जी, आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जहां जरूरत से ज्यादा भीड़ लगने लगी है। इसमें भीड़—भाड़ कम करने के लिए हमने टीकरी खामपुर में 70 एकड़ में आधुनिक मंडी बनाने का फैसला किया है। इस पर 800 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और इस परियोजना के दिसंबर 2019 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

109. हमने गाजीपुर में 150 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक फूल मंडी और प्रदर्शनी केन्द्र विकसित करने का फैसला किया है ताकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक केन्द्र के रूप में विकसित हो सके। यह मंडी न सिर्फ व्यापार केन्द्र का कार्य करेगी, बल्कि जनता भी यहां आकर फूलों की खूबसूरती का आनंद उठा सकेगी जिससे पुष्प उत्पादन और पर्यटन दोनों को ही बढ़ावा मिलेगा।

110. हम गाजीपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मछली और पोल्ट्री बाजार का भी विकास करेंगे जिस पर 120 करोड़ रुपये लागत आयेगी। गाजीपुर के इस मछली—मुर्गा बाजार में कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र भी लगाया जाएगा। यह परियोजना 2017—18 में पूरी हो जाएगी।

111. हमारी सरकार सभी मंडियों में ई—मंडी परियोजना लागू करने को वचनबद्ध है ताकि लेन—देन में पारदर्शिता आए, उत्पादकों को बेहतर दाम मिलें और उन्हें अपने उत्पादों के भुगतान में कम समय लगे। हम राष्ट्रीय कृषि बाजार के ई—पोर्टल में शामिल होकर चरणबद्ध तरीके से दिल्ली में ई—मंडी परियोजना लागू करेंगे।

112. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार तमाम समुदायों की संस्कृति और धार्मिक रीति–रिवाजों का सम्मान करने को प्रतिबद्ध है। अपनी इसी प्रतिबद्धता के क्रम में हमने समूची दिल्ली में छठ घाट बनाने का फैसला किया है। वित्त–वर्ष 2017–18 में दिल्ली में छठ घाटों के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

113. मैं 2017–18 में ग्रामीण विकास और बाढ़ व सिंचाई के लिए कुल 925 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 251 करोड़ रुपये का राजस्व बजट और 674 करोड़ रुपये का पूंजी बजट शामिल है। ग्रामीण विकास और बाढ़ व सिंचाई क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 704 करोड़ रुपये के खर्च का आबंटन किया गया है।

पर्यटन

114. अध्यक्ष जी, दिल्ली देश के समृद्ध अतीत और फलते–फूलते वर्तमान का प्रतीक है, जहां प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वित रूप देखने को मिलता है। दिल्ली को एक पर्यटन नीति की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। दिल्ली को पर्यटकों के आकर्षण का विश्व स्तरीय केंद्र बनाने और दिल्ली पर्यटन के लिए ढांचा और अन्य सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम पर्यटन नीति और मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं।

115. दिल्ली को फिल्म शूटिंग के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एक ''सिंगल विंडो मंजूरी व्यवस्था'' शुरू करने का प्रस्ताव है ताकि शहर में फिल्म निर्माण और शूटिंग संबंधी कानूनी औपचारिकताएं केवल एक सरकारी कार्यालय में पूरी की जा सकें। फिल्म निर्माताओं को मंजूरी प्रदान करने और उन्हें शूटिंग के नियमों के बारे में समेकित जानकारी प्रदान करने और फिल्म शूटिंग को एक बाधारहित अनुभव बनाने के लिए एक सुचारू प्रणाली विकसित की जा रही है।

116. हमने गार्डन आफ फाइव सेंसेस में एक पर्यावरण अनुकूल परियोजना के रूप में साफ्ट एडवेंचर पार्क विकसित किया है, जिसके चारों ओर आकर्षक हरित उद्यान फैला हुआ है और जो एडवेंचर पार्क को एक जादुई परिवेश प्रदान करता हैं। गार्डन आफ फाइव सेंसेस में इस साल कई तरह की गतिविधियां आयोजित की गई। एक दिन में 15,000 से ज्यादा फुट–फाल्स इस साल देखे गये। 2017–18 में गार्डन आफ फाइव सेंसेस को नाईट लाईफ व लग्जरी फूड कोर्ट का हब बनाने का प्लान है।

117. अध्यक्ष जी, दिल्ली को विश्व स्तरीय पर्यटक शहर के रूप में विकसित करने का काम जारी रखते हुए हमने यमुना नदी के किनारों के विकास की योजना बनाई है। इसका लक्ष्य एक ऐसे स्थल का विकास करना है, जहां लोग अपने को प्रकृति और यमुना नदी से जुड़ा हुआ महसूस करें और नदी के महत्व और उसके संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़े और वे नदी में सुधार के लिए प्रयास करें। इससे जल निकायों के साथ ऐसी आर्द्र भूमि का विकास किया जा सकेगा, जो भूमिगत जल के पुनर्भरण और नदी की स्थिति में सुधार लाने में सहायक हो। इससे नदी को प्रदूषण से बचाने और वन्यजीवों को सहारा देने वाले स्थानीय तथा वातावरण के अनुकूल पौधों की विविध प्रजातियों के विकास में मदद मिलेगी। पांच किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास इकोलोजिकल रिवर फ्रंट वजीराबाद के अपस्ट्रीम में बनाने का प्रस्ताव हम पेश कर रहे हैं।

118. मैं वर्ष 2017–18 में पर्यटन के लिए कुल 119 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें 69 करोड़ रुपये का राजस्व बजट और 50 करोड़ रुपये का पूंजी बजट शामिल है। पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 117 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं।

119. मैं अब अपने भाषण का भाग 'ख' प्रस्तुत करता हूं।

भाग 'ख'

120. माननीय अध्यक्ष जी, अपने भाषण के प्रथम भाग में मैंने सरकार की नीतियों की विस्तार से चर्चा की है। मैं यह बात दोहराना चाहता हूं कि यह सरकार दिल्ली के आम जनों की, आम आदमी द्वारा बनायी गई और आम आदमी के लिए है। पिछले दो वर्षों से हम कर–मुक्त बजट पेश करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है और न ही किसी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव है।

121. माननीय सदस्यों को मालूम है कि वस्तु और सेवा कर, यानी जीएसटी का अनुमोदन हो चुका है और 1 जुलाई, 2017 से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका असर सरकार के कर–राजस्व की वसूली पर पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए राजस्व–कर की वसूली 38,700 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2016–17 के 32430 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों से 19.33 प्रतिशत अधिक है। यह अनुमान इस विश्वास पर आधारित है कि जीएसटी लागू होने से कर में तेजी या उछाल (buoyancy) आयेगा। इन सब घटकों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है।

122. अध्यक्ष जी, हमने वर्ष 2015–16 में इमारती लकड़ी यानी टिम्बर पर कर की दर में कमी की थी। दूसरे वर्ष भी अनेक वस्तुओं पर कर की दरें घटाई गई थीं। इस वर्ष हम निम्नांकित वस्तुओं पर कर की दरों में कमी करने का प्रस्ताव कर रहे हैं:

(क) 20 रुपये मूल्य तक के सेनेटरी नेपकिन्स कर–मुक्त हैं। महिलाओं की स्वच्छता के प्रति सरकार के सरोकार को देखते हुए 20 रुपये से अधिक मूल्य वाले सेनेटरी नेपकिन्स मामले में कर की मौजूद दर 12.5 प्रतिशत है, जिसे कम करके मात्र 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

(ख) लेमिनेट्स, प्लाईवुड और ब्लैक बोर्ड, एमडीएफ बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड के लिए मौजूद 12.5 प्रतिशत की दर को कम करके मात्र 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

(ग) पिछले वर्ष मार्बल पर कर की दर घटाकर 5 प्रतिशत की गई थी, इस वर्ष ग्रेनाइट, स्वदेशी कोटा स्टोन, धोलपुर स्टोन, ग्वालियर स्टोन स्लेट पर भी कर की दर मौजूद 12.5 प्रतिशत से कम करके मात्र 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

123. क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम यानी आरसीएस (उडान) के अंतर्गत विमान प्रचालन करने का विकल्प अपनाने वाले और स्कीम के अनुसार निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद भारत के भीतर (दिल्ली सहित) उड़ान के प्रारंभ स्थान और उतरने के स्थान के हवाई अड्डों/हेलिपेडों से दो चुने हुए स्थानों के बीच आरसीएस मार्गों पर प्रचालन करने वाले नागर विमानन ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए एयर टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की खरीद पर वैट की दर मौजूद 25 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

124. यह सम्मानित सदन इस बात से अवगत है कि हमारी सरकार व्यापारियों के अनुकूल सरकार है और पहले दिन से ही हमारी यह कोशिश रही है कि दिल्ली में व्यापारियों के लिए मददगार वातावरण पैदा हो। अतः तदनुरूप एक विशेष अभियान चलाया गया है और मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चालू वर्ष के दौरान 723 करोड़ रुपये रिफंड किए गए, जो पिछले वर्ष के 227 करोड़ रुपये रिफंड की तुलना में 300 प्रतिशत अधिक है। कुल मिलाकर 72000 रिफंड के मामलों का निबटारा किया गया।

125. अध्यक्ष जी, इन शब्दों के साथ, मैं सदन के विचारार्थ बजट को प्रस्तुत करता हूं।